श्री रमेश पोखरियाल "निशंक": श्रीमन्, चूंकि अभी ऐक्ट पारित हुआ है, इसलिए हम उसके स्थान और भवन की व्यवस्था करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यथासंभव उसको जल्दी शुरू करें।

SHRI K.J. ALPHONS: Would the Government of India take initiative to start a national law school in Kerala?

MR. CHAIRMAN: From Kashmir, you have gone to Kerala. The question is specific. Mr. Minister, keep the suggestion in mind.

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" श्रीमन्...

श्री सभापति: आप इसको संज्ञान में लीजिए। आप बाद में एल्फोंस जी को बुलाकर यह पूछ लीजिएगा कि उनका क्या सुझाव है।

Kitchen garden projects in schools

*117. SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all schools have been asked to prioritise kitchen garden projects to be maintained by the students; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Under Mid-Day Meal Scheme all the States and UTs are being encouraged to set up School Nutrition (Kitchen) Gardens. Various stakeholders *viz.* teachers, students, parents and even local residents are involved in development and maintenance of these Gardens. These Gardens are places where fruits and vegetables are grown in the school premises, which may be used in preparation of mid-day meal. Purpose of School Nutrition (Kitchen) Gardens is to give children first-hand experience with nature and gardening. They can learn about balanced diet and organic methods of growing fruits and vegetables, as per the geographical situation and need of the school.

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्कूलों के अंदर उन्होंने किचेन गार्डन का प्रावधान दोपहर के भोजन की योजना के अंतर्गत रखा। मेरा इसमें यह मानना है कि vertical vegetable garden, वह स्कूलों की दीवारों के ऊपर लग सकता है,

जहाँ पर जगह की कमी है, जैसे दिल्ली के अंदर सरकार ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर लगाया है। Moveable vertigrow kitchen garden, जो पहियों पर चल सकता है, वह चार फीट का गार्डन 200 वर्ग फीट के एरिया में जितना लग सकता है, स्कूलों में लगाया जा सकता है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Right.

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सर, मेरा क्वेश्वन यह है कि ऐसे गार्डन्स, जो कि क्लासरूम में, प्लेग्रांउंड में और रिसेप्शन पर घूमकर जा सकता है, को लगाने के लिए क्या आप सीबीएसई के स्कूल्स को कुछ ग्रांट देने की योजना बना रहे हैं, ताकि यह प्रमोट हो सके?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" : श्रीमन्, यह बहुत ही अच्छी योजना है। किचेन गार्डन के माध्यम से बच्चों में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, उसमें हम मदद करेंगे। प्रकृति और बागवानी के साथ बच्चों का कैसे अनुभव हो सकेगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सब्जियों के पोषण से संबंधित पहलों के बारे में वृहत जानकारी करेंगे। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस समय 11 लाख 23 हज़ार 920 स्कूल्स में पूरे देश के अंदर किचन गार्डन चल रहे हैं। पहले चरण में हमने 2 लाख 42 हज़ार 978 शुरू कर दिए हैं। हम प्रति किचन गार्डन को 5,000 रुपये दे रहे हैं। दूसरी ओर हमने ईको क्लब का भी गठन किया है, ताकि ये दोनों संयुक्त रूप में समग्र शिक्षा के तहत अच्छी योजना बन सके।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे आप सीओए के माध्यम से भूमि की सीमा तय कर देते हैं और स्टेट उस पर अप्रूवल देता है। इसी प्रकार से स्कूल्स में..., आप जैसे हरियाणा में कहीं किसी जिले में...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सर, मैं सवाल ही कर रहा हूं। कहीं एक एकड़ में स्कूल है तो कहीं 5 एकड़ में बना सकते हैं, उससे कम पर नहीं बना सकते हैं। आज आरटीई के तहत स्कूल्स की बहुत कमी है।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: आपने जो एक एकड़ पर सीनियर सेकण्डरी स्कूल की सीबीएसई की योजना की है, क्या पूरे देश में आप भूमि के नियम को समरूप करना चाहेंगे?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक": श्रीमन्, सीबीएसई बोर्ड के अपने मानक हैं, चूंकि सीबीएसई बोर्ड को अपने मानकों के आधार पर उन विद्यालयों की गुणवत्ता बरकरार रखनी होती है इसलिए उन्होंने अपने मानक बनाए हैं कि वे शिक्षा को कैसे सशक्त करके व्यवस्थित कर सकते हैं इसीलिए उनके मानकों पर आना पड़ेगा।

चौधरी सुखराम सिंह यादव: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय

मंत्री जी प्रदेश सरकारों को इस बात के निर्देश देंगे कि जिन विद्यालयों में किचन गार्डन नहीं हैं, उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी?

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक": श्रीमन्, इस निर्देश में बहुत स्पष्ट है कि यथासंभव, यदि ½ भी है, यदि छोटे-छोटे डिब्बों में भी लगा सकते हैं, यदि स्कूल की छत पर भी लगा सकते हैं, उसके बगल के रास्ते पर भी लगा सकते हैं तो लगाइए। इसमें व्यापकता है। आज देश के अंदर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है, जो इसका पालन नहीं कर सकता है।

Examination fee hike for classes X and XII

*118. KUMARI SELJA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Board of Secondary Education (CBSE) has increased the examination fee for Classes X and XII by 2300 per cent for five subjects for SC/ ST students and from ₹750 to ₹ 1500 for general category students;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether SC/ST students will now have to pay ₹ 300 for appearing in any additional subject in Class XII Board examinations;

(d) whether fee to appear in any additional subject in Class XII Board examinations is the same for SC/ST students and general category students; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Central Board of Secondary Education (CBSE) has increased the examination fees of Class X and XII Board examination 2020, on no profit no loss principle, from ₹ 750/- to ₹ 1500/- for all categories of students, including SC/ST candidates for all schools in whole of India, except for schools of Delhi Government. For 1299 schools of Delhi Government, examination fee for all categories of Class X students has been increased from ₹375/- to ₹ 1200/- and for Class XII students from ₹ 600/- to ₹ 1200/-. Thus, the examination fee for Class X and Class XII has not been increased by 2300 per cent. CBSE is a self financed and self-reliant Board and generates its own resources. It does not take any funds from the Consolidated Fund of India or any other authority for its expenses.